एमएसएमई की बदली परिभाषा निवेश व रोजगार में नई आशा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एमएसएमई को देश का महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन बताते हुए इसकी परिभाषा में बदलाव की घोषणा की है। इससे एमएसएमई को अपने विस्तार करने का मौका मिलेगा, जिससे नए रोजगार की संभावनाएं निकलेंगी। 500 करोड़ तक की सालाना टर्नओवर वाली कंपनियां अब मीडियम श्रेणी में आएंगी और एमएसएमई से जुड़ी स्कीम का लाभ ले सकेंगी। जाहिर तौर पर उन्हें बड़ा फायदा होगा। बजट में एमएसएमई के लिए महत्वपूर्ण कर्ज की समस्या को भी दूर करने की कोशिश की गई है। बैंकों से कर्ज लेने की सबसे अधिक दिक्कत माइक्रो एमएसएमई को होती है और इसके समाधान के लिए वित्त मंत्री ने माइक्रो इंटरप्राइजेज को किसानों की तरह पांच लाख तक की सीमा वाले क्रेडिट कार्ड जारी करने का एलान किया है। हालांकि इस सुविधा का लाभ एमएसएमई मंत्रालय के उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत माइक्रो उद्यमियों को ही मिल सकेगा। मैन्यूफैक्चरिंग व सर्विस सेक्टर को मिलाकर देश में 5.7 करोड़ एमएसएमई है, लेकिन इनमें से करीब एक करोड़ एमएसएमई ही उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। हालांकि एमएसएमई को वैश्विक वैल्यू चेन से जोड़ने की कोई घोषणा नहीं की गई है।

45%

का योगदान एमएसएमई का है देश के निर्यात में

125 करोड़ के निवेश और 500 करोड़ के टर्नओवर वाले मीडियम इंटरप्राइजेज होंगे

2.5 करोड़ रुपये के निवेश और 10 करोड़ टर्नओवर वाले उद्यमी माइक्रो श्रेणी में आएंगे